



- वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वह नागरिकों तक जीएसटी के लाभों के हस्तांतरण पर व्यक्तिगत रूप से नज़र रखेंगी।
- केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा – नई लागू की गई जीएसटी दरों और स्लैब से छोटे और मध्यम किसानों को लाभ होगा।
- प्रदेश कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष ने मुख्य सचिव से स्कूलों में शैक्षणिक प्रणाली में कमियों को दूर करने का आग्रह किया है।
- राष्ट्रीय पोषण माह के अवसर पर कल से योग सत्र का आयोजन किया जाएगा।



वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वह नागरिकों तक जीएसटी के लाभों के हस्तांतरण पर व्यक्तिगत रूप से नज़र रखेंगी। वित्त मंत्री ने कहा कि देश भर के लोगों ने जीएसटी सुधारों को एक स्वागत योग्य कदम बताया है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि अगर उन्हें लाभ नहीं मिल रहा है तो वे इसकी सूचना दें। उन्होंने आगे कहा कि कई उद्योग जगत के दिग्गजों ने पहले ही लाभ पहुंचाने का वादा किया है।

केंद्र सरकार का कई प्रमुख क्षेत्रों में जीएसटी में व्यापक कटौती का सीधा असर सहकारी समितियों, किसानों और ग्रामीण उद्यमों पर पड़ेगा। इसका लाभ देश के दस करोड़ से ज़्यादा डेयरी किसानों को मिलेगा। सहकारिता मंत्रालय ने कहा है कि ये ऐतिहासिक सुधार सहकारी क्षेत्र को मज़बूत करेंगे और उत्पादों को प्रतिस्पर्धी बनाएंगे। इससे उत्पादों की मांग बढ़ेगी और सहकारी समितियों की आय में वृद्धि होगी। ये सुधार ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देंगे और लाखों परिवारों को सस्ती आवश्यक वस्तुएं सुलभ करेंगे।



केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि नई लागू की गई जीएसटी दरों और स्लैब का कृषि क्षेत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। कल भोपाल में एक संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इन बदलावों से विशेष रूप से छोटे और मध्यम किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि कृषि उपकरणों पर जीएसटी दरों में कमी से खेती की लागत कम होगी और किसानों का

लाभ बढ़ेगा। श्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जैव-कीटनाशकों और सूक्ष्म पोषक तत्वों पर जीएसटी कम कर दिया गया है, जिससे न केवल किसानों को लाभ होगा, बल्कि रासायनिक उर्वरकों से जैव-उर्वरकों की ओर रुझान को भी बढ़ावा मिलेगा। डेयरी क्षेत्र में, दूध और पनीर पर जीएसटी हटाने से न केवल उपभोक्ताओं को लाभ होगा, बल्कि किसानों, पशुपालकों और दुग्ध उत्पादकों को भी महत्वपूर्ण राहत मिलेगी। श्री चौहान ने यह भी बताया कि कृषि से जुड़े अन्य क्षेत्र, जैसे पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन, कृषि वानिकी और मुर्गी पालन, जीएसटी छूट से काफ़ी लाभान्वित होंगे। उन्होंने आगे कहा कि यह कृषि अर्थव्यवस्था को और मज़बूत करेगा। ये सुधार कई महिलाओं, जिनमें लखपति दीदी भी शामिल हैं, को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करेंगे, जिससे उनकी आय बढ़ेगी और इस आंदोलन को नई गति मिलेगी।



चिन्मय मिशन की ओर से पितृपक्ष के अवसर पर आज से श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा का आयोजन किया जा रहा है। मिशन के सभागार में चौदह सितंबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम का शुभारंभ आज सुबह साढ़े सात बजे कलश यात्रा के साथ होगा। कल से तेरह सितंबर तक प्रतिदिन शाम चार से आठ बजे तक कथा वाचन किया जाएगा। चौदह सितंबर को सुबह दस बजे पूर्णाहुति होमम्, भजन और अन्नदानम का आयोजन किया जाएगा। चिन्मय मिशन ने सभी से इस अनुष्ठान में भाग लेने का अनुरोध किया है।



अंडमान निकोबार प्रदेश कांग्रेस समिति की प्रचार समिति के अध्यक्ष टीएसजी भास्कर ने मुख्य सचिव से द्वीपसमूह के स्कूलों में शैक्षणिक प्रणाली में कमियों को दूर करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया है। उन्होंने अपने लिखे पत्र में कहा कि द्वीपों के कई सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में विशेष शिक्षकों, परामर्शदाताओं और वाक चिकित्सकों की उपलब्धता की कमी पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 का उल्लंघन होता है। श्री भास्कर ने स्कूलों में विशेष शिक्षकों और सहायक पेशेवरों की वर्तमान उपलब्धता का तत्काल आंकलन करने, भर्ती के लिए राष्ट्रीय बहुदिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान जैसे विशेषज्ञ संस्थानों के साथ सहयोग करने और समावेशी शिक्षा से संबंधित एनईपी 2020 के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने का आग्रह किया।



राष्ट्रीय पोषण माह मनाए जाने के सिलसिले में पुरुषों में मोटापे के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए एक सप्ताह का योग सत्र आयोजित किया जा रहा है। यह सत्र कल से पन्द्रह सितंबर तक सुबह पांच बजे से छः बजे तक जंगलीघाट स्थित आयुष अस्पताल के योग इकाई और मरीना पार्क में आयोजित किया जाएगा। इस सत्र में योगाभ्यास, व्यायाम और जीवनशैली संबंधी जानकारी दी जाएगी। स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा द्वीपसमूह के पुरुषों में जीवनशैली संबंधी बीमारियों की रोकथाम को प्रोत्साहित करने के लिए नियमित योगाभ्यास, संतुलित पोषण और शारीरिक गतिविधि के महत्व पर भी सत्र आयोजित किए जाएंगे।



अंडमान निकोबार प्रशासन ने अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के छात्रों को प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए वे ओ बी सी छात्र आवेदन कर सकते हैं, जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय ढाई लाख से कम है। प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए डॉ अम्बेडकर पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति द्वीपसमूह के ओ बी सी छात्रों को माध्यमिक स्तर के बाद भारत में कहीं भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, जिनकी वार्षिक आय आठ लाख रुपये से कम है। सभी पात्र उम्मीदवारों से इक्कीस अक्टूबर तक राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने को कहा गया है।



टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय में शैक्षणिक सत्र दो हजार पच्चीस-छब्बीस के लिए दो वर्षीय बी. एड. डिग्री कार्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की अंतिम वरीयता सूची कल शाम चार बजे जारी की जाएगी। परामर्श दस तारीख को और कक्षाएं ग्यारह सितम्बर से आरंभ होगी। बची हुई सीटों के लिए दूसरे चरण का परामर्श बारह सितम्बर को आयोजित किया जाएगा। इस संबंध में अधिक जानकारी सामान्य कॉलेज प्रवेश पोर्टल पर उपलब्ध है।



शैक्षणिक सत्र दो हजार पच्चीस-छब्बीस के लिए द्वीपसमूह के छात्रों के लिए मुख्य भूमि संस्थानों में बी.एस.सी कृषि, बी.एस.सी बागवानी, बी.एफ.एस.सी और बी.टेक मत्स्य इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के लिए परामर्श कल सुबह दस बजे से टैगोर कॉलेज के सभागार में आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों से अपने मूल दस्तावेजों के साथ परामर्श में उपस्थित रहने को कहा गया है।



युवा मामले और खेल मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से श्री विजयपुरम में बीस सितंबर को अस्मिता रग्बी सेवेन्स लीग का आयोजन किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य देश भर में विभिन्न आयु वर्ग की महिला एथलीटों को प्रतिस्पर्धात्मक अवसर प्रदान करना है। इस लीग में भाग लेने के लिए इच्छुक टीमों पन्द्रह सितम्बर तक नेताजी स्टेडियम स्थित राज्य ओलंपिक कार्यालय में पंजीकरण करा सकती हैं। इसके अलावा, यदि किसी टीम को प्रशिक्षण और टीम निर्माण के लिए कोच की आवश्यकता होती है, तो एसोसिएशन की ओर से निःशुल्क कोचिंग सहायता प्रदान किया जाएगा।



जिला प्रशासन की ओर से कल अट्टम पहाड़ क्षेत्र में अतिक्रमण अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान, राजस्व टीम ने लगभग पांच हजार वर्ग मीटर सरकारी भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराया। आठ अस्थायी आवासीय ढाँचों के साथ कई अनधिकृत बाड़ों को हटाकर उसकी मूल स्थिति में बहाल कर दिया गया। जिला प्रशासन ने आम जनता से अवैध अतिक्रमणों से दूर रहने की अपील की है।

